an>

Title: Problems faced by the people of Darjeeling due to prevailing unrest.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं देश का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठा रहा हूं। पिछले एक महीने से ज्यादा दार्जिलिंग, जो बंगाल का मुकुट माना जाता है, में हिंसा भड़की है, गतिरोध चल रहा है। यह देश की एकता का सवाल है। पिछले एक महीने से ज्यादा हो गया है कि पुलिस की गोली से दार्जिलिंग में एजिटेट करने वाले मारे जा रहे हैं। यहां राशन बंद किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि यह बंगाल का हिस्सा है और यह देश की एकता और अखंडता का भी सवाल है। जनता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते हैं। वहां के खाद्य मंत्री घोषणा कर रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं कि हम राशन रोक देंगे। राइट टू फूड के अधिकार के तहत हम किसी का खाना-पानी नहीं रोक सकते हैं।

इसके बाजू में सिक्किम है, अलग प्रांत है, सड़क वहीं से गुजरती है, गतिरोध के कारण वहां की जनता को भी परेशानी हो रही है। गोरखा टेरिटोरियल अथारिटी बनी थी, ट्राईपार्टाइट बैठक हुई थी, केंद्र, राज्य और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच हुई थी। छः साल पहले यह मामला हुआ था, उसमें यह लिखा था कि निरंतर प्रयास चलेगा, हम रिव्यु करेंगे कि किस तरह से वह फंक्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आज क्या हो रहा है? जीटीए के इलैक्टिड मैम्बर्स के घर में पुलिस भेजकर वहां की सरकार कहती है कि हम औजार निकालकर लाए हैं। इलैक्टिड गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल सैल्फ गवर्नमेंट हो, म्युनिसिपल कापरिशन हो, जैसे त्रिपुरा में बनाई गई है, उसी तरह से देश के अन्य प्रांतों में जो भाषाई रूप से अलग हैं, कन्टीगुअस एरिया हैं, खासकर ऑटोनोमस काउंसिल जीटीए इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि ट्राइबल एरिया को राज्य और देश की एकता को ध्यान में रखकर स्वायत शासन देना पड़ेगा।

यह एथनिक सवाल है, भाषा का सवाल है, तारीख का सवाल है, सिर्फ जियोग्राफी का सवाल नहीं है। वहां पर जोर जबरदस्ती भाÂषा लादने के नाम पर मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे कदम उठाए कि दखल करने का माहौल बना, सबमें दखल करना पड़ेगा, विरोधी पक्ष नहीं रहेगा, पंचायत में दखल कर लो, जीटीए में दखल कर लो, उनके दफ्तर में दखल कर लो, उनकी पंचायत में दखल कर लो। दखल, ...* और प्रशासन लोकतंत्र को हथिया लेंगे।

माननीय अध्यक्ष : ... * शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री मोहम्मद सलीम : यह दार्जिलिंग में ही सीमित नहीं है। आज डुआर्स से लेकर उत्तर बंगाल में समस्या बढ़ रही है। केंद्र सरकार चुपचाप खामोशी से तमाशा नहीं देख सकती है। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। ट्राईपार्टाइट बैठक बुलाइए, शांति की बहाली कीजिए, वहां लोग मर रहे हैं, उनको बचाइए, उनका राशन बंद किया जा रहा है। उनको इसके लिए मना कीजिए और मुख्यमंत्री को बताइए कि संविधान के अनुसार काम करें, कानून के अनुसार काम करें, वे जबरन किसी का अधिकार छीन नहीं सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष:

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री पी.के. बिजू,

श्री शंकर प्रसाद दत्ता,

डॉ. ए. सम्पत और

एडवोकेट जोएस जार्ज को श्री मोहम्मद सलीम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, दार्जिलिंग की स्थिति के बारे में भारत सरकार चिंतित है। अभी माननीय सदस्य मोहम्मद सलीम जी ने वहां की स्थिति सदन में उजागर की है। दार्जिलिंग की स्थिति बहुत ही विकट बनती जा रही है। वहा शांति पुस्थापित होनी चाहिए। यदि उस शांत पहाड़ को आग लग चुकी है, तो यह पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री जी का रवैया और उन्होंने इस समस्या को जिस तरह हैंडल किया, उस कारण है।

अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार का अनुरोध है कि वहां पहले शांति और कानून व्यवस्था पुस्थापित की जाये। उसके बाद वहां की जो डिमांड है, उस बारे में हम सब मिलकर चिंता कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ...(व्यवधान)